UD|94|11422, dated the 24th October, 1994. (Placed in Library. See No. LT-7692/95].

Message from the Lok Sabha

The Recovery of Debts due to the banks and Financial Institutions (Amendment) Bill, 1995

SECRETARY GENERAL: Madam, I have to report to the House the following message received fro mthe Lok lowing message received from the Lok Sabha signed by the Secretary General of the Lok Sabha:

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions (Amendment) Bill 1995 as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 30th May, 1995."

Madam I lay the Bill on the Table.

REPORT OF THE COMMITTEE ON .. SUBORDINATE LEGISLATION

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Madam, I present the Hundred and Twelfth Report (in English and Hindi) of the Committee on Subordinate Legislation.

REPORT OF THE DEPARTMENT-RELATED PARLIAMENTARY STAND-.ING COMMITTEE ON COMMERCE.

SHRI M. RAJASEKARA MURTHY (Karnataka): Madam, I present the Fourteenth Repprt in English and Hindi) of the Department Related Parliamentary Standing Committee on Commerce, on Sericulture.

REPORT AND MINUTES OF THE STANDING COMMITTEE ON ENERGY

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Madam, I lay on the Table a copy (in English and Hindi) of the Twenty-sixth Report of the Standing Committee on Energy on "New Policy initiatives in Power Sector-Status of implementation and thehir impact on the economy" and Minutes of the Sittings of the Committee relating thereto

---

REPORT OF THE JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

SHRI SARADA MOHANTY (Orissa): Madam, I lay on the Table a copy (in English and Hindi) of the Eighth Report of the Joint Committee on Offices of Profit.

REPORT OF THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE

SHRI T. VENKATRAM REDDY (Andhra Pradesh): Madam, I lay on the Table a copy (in English and Hindi) of the Fifteenth Report of the Standing Committee on Finance on 'The Union Duties of Excise (Distribution) Amendment Bill, 1995'.

RE. ENTRY OF FAST FOOD COMPANIES INTO INDIA

उपसभापति : श्री दिग्विजय सिंह । जरा फास्ट बोलिएगा । . . . (**व्यवधान**) ।

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Madam, I also want to raise an important point.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Satya Prakash Malaviaji also wants to raise a point.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Madam, I want to raise something else.

उपसभापति : दिग्विजय सिंह जी, एक दम फास्ट फूड के बारे में बोल रहे हैं।

श्री दिग्विजय सिंह (बिहार) : उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि अभी सरकार ने विदेशी मल्टी-नेशनल कम्पनियों को इस देश में खाना बनाने की इजाजत दी है, जिसे हम फास्ट फूड कहते हैं। मैं इसके पहले आपसे यह कहूं कि यह फास्ट फूड कैसी फ्राइड चिकन, पिजा हट, पैप्सी फूड्ज, ये अभी 60 पैप्सी फूड्ज को, 30 पिजा हट्स को, 30 कैफू फ्राइड चिकन को दी गई हैं, मैकडोनल आने वाला है और जो उम्मीद है, वह 5,000 के आस-पास रेस्तरां खोलने की इजाजत इन विदेशी कम्पनियों को दी जा रही है।

मैं इस खाने के विरोध में इसलिए हूं कि आज दुनिया के जो दूसरे देश हैं, जहां यह खाने बनते थे, वहां आज इस को जर्म फूड कहा जा रहा है और इसके खिलाफ एक बड़ा आन्दोलन चल रहा है। इन देशों में, खासकर के अमरीका में, पश्चिमी देशों में यह आन्दोलन चल रहा है और इसलिए जो गरीब मुल्क हैं, वहां यह कम्पनियां आ रही है।

उपसभापति महोदया, उससे भी खतरनाक बात यह है कि अभी 20-21 मई को बी.बी.सी. से एक अमरीकन सर्वे आया था, डाक्यूमेंटरी फिल्म के तहत, उस में कहा गया है कि अमरीका में 8 करोड लोग हृदय रोग से परेशान हैं, इन खानों की वजह से। जब तक यह खाने अमरीका में नहीं आए थे, तब तक यह रोग अमरीका में प्रचलित नहीं था। आज 8 करोड़ लोग अमरीका में इन खानों से बीमार हैं और सिर्फ हृदय रोग से बीमार हैं। क्या यह गरीब लोग ऐसे रोगों का शिकार बनेंगे? क्या इस देश में बर्बादी और तबाही के कारण यह खाने बन सकते हैं या नहीं?

महोदया, जो इसके और नतीजे बताए गए हैं इस रिपोर्ट में, वह और भी भयानक है। सबसे भयानक बात तो यह है कि इन कम्पनियों का दावा है कि जो इनकी मुर्गियां, इनके मुर्गे खाना खायेंगे, वह हिन्दुस्तान के आम आदमी को नहीं मिल रहा। एक मुर्गी को बनाने के लिए तीन किलो वजन का हमारा जो प्रोटीन युक्त खाना है, भुट्टा जैसे है, जैसे सोयाबीन है, यह उनको खिलाया जाएगा। अब आप देखिए, इस मुल्क में लोगों को दो जून रोटी नहीं मिल रही, यहां प्रोटीन की कमी से बच्चे, बच्चियां अपाहिज पैदा हो रहे हैं, उस मुल्क में मुर्गी को तीन किलो भुट्टा, सोयाबीन खिलाया जाएगा। ...(**व्यवधान**).. जी, सोयाबीन तेल तो नहीं मिल रहा।

एक और बात, महोदया, यह उभर कर सामने आई है, इस रिपोर्ट से, कि ऐसे जानवरों के लिए, जो जानवर इन खानों में इस्तेमाल किए जायेंगे, उन जानवरों के लिए दस गुना पानी की जरूरत है। आज जैसलमेर, बाड़मेर में लोग प्यासे मर रहे हैं, बिहार में, कालाहांडी में पानी नहीं मिल रहा, लेकिन ऐसे जानवरों के लिए मनुष्य से दस गुना ज्यादा पानी की जरूरत होगी। यह भी इस रिपोर्ट में आया है।

अगली बात, जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, उपसभापति महोदया, वह यह कि यह जो सर्वे आया है, जो रिपोर्ट आई है, इसमें भेड़ बकरे का इस्तेमाल होगा, उसके साथ पर्यावरण का सवाल जुड़ा हुआ है। ऐसे भेड़, बकरों को खिलाने के लिए करीब चार हैक्टेयर जमीन की जरूरत पड़ती है। तब जाकर ग्रीनरी वह खाएंगे, उनको पौष्टिक आहार मिलेगा और तब यह सुचारु रूप से अपने फ्रायड चिकेन, केनची फ्रायड चिकेन, पैप्सी फूड, डाक डोनाल्ड इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या हिन्दुस्तान जैसा मुल्क, हिन्दुस्तान के लोग ऐसी चीजों को बर्दास्त कर पाऐंगे या नहीं कर पाऐंगे? यह चन्द अमीर लोगों के बच्चों के लिए,

[श्री दिग्विजय सिंह]

चन्द अमीरों के भोग विलास के लिए इस देश की तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हमारे अपने पेटेण्ट का मामला चल रहा है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि पेटेण्ट कराना ही था, प्रसार कराना ही था, प्रचार कराना ही था, तो हमारे अपने देश की सभ्यता और संस्कृति के जो खाने थे, उनका कराते, जैसे दक्षिण का इडली, साभर बड़ा, डोसा, इधर का पूड़ी, कचौड़ी, हलवा, ऐसा बढ़िया भोजन मिल सकता था। क्यों ऐसे लोगों को, ऐसी कम्पनियों को बुलाकर इस देश में न्यौता दिया जा रहा है ?....*(व्यवधान)*...

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा) : ऐसे खाने तो ताजे रहते हैं, रखने वाले हैं, जैसे मट्ठी, लड्डू, पिन्नी, खाखरा, यह सारे खाने हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : हमारे देश में तो ऐसे ही विभिन्न तरीकों के भोजन हैं, जो दुनियां में पसन्द किए जाते है। आज आप दुनियां में कहीं चले जाइए मैं तो दुनियां के जिस देश में जाता हूं तो वहां पाता हूं कि भारतीय खाने की होड़ लगी रहती है। टोक्यो शहर में तो तीन-तीन दिन तक खड़े रहना पड़ता है, वहां के रेस्टोरेंट में, तब जाकर आपका नम्बर आता है।

महोदया, जहां हमें अपने खाने का विकास करना चाहिए था, अपने खाने का दुनियां में प्रचार करना चाहिए था, वहीं हम दुनियां से ऐसे सड़े गले पदार्थ को अपने देश में लेकर इस देश की सभ्यता को नष्ट करेंगे, इस देश की गरीबी और अमीरी की खाई को बढ़ाएंगे, जिसे हमारे देश के लोग बर्दास्त नहीं कर पायेंगे। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इनको रोकने के लिए जल्द से जल्द इन्तजाम किया जाए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया, मुझे लगता है कि सारा सदन इसमें साथ होगा। मैं सम्बद्ध करती हूं, इनसे अपने आपको।....*(व्यवधान)*.... रेड्डी साहब, आप भी इसमें एसोसिएट कर रहे हैं ? इनके बाद मैं भी एसोसिएट करूंगी।

SHRI S. JAIPAL REDDY (Andhra Pradesh): Madam, I have come to know that the Government has allowed the opening of 60 outlets of Mac Donald's, 40 outlets of Pizza Hut and 20 outlets of Kentucky fried chicken. In all, there will be 120 outlets in various metropolitan cities of India.

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): It is only a beginning.

SHRI S. JAIPAL REDDY: As Mr. Jagesh Desai is rightly pointing out, it is only a beginning. It is the thin end of the wedge.

Madam, the first thing to be noted is that the rich who are going to pay visits to these outlets are going to pay in rupees, but the nation will have to pay to them in dollars. Are we suffering from excess of dollars? Are they believing that our foreign exchange reserves, which we have built up to twenty thousand dollars, are really unassailable? I would like the Government to address itself to this question.

Madam, he referred to our own vegetarian preparations. I have, of late, become vegetarian, but for a long time I have been a non-vegetarian. Some of our non-vegetarian preparations like *Tandoori* chicken or *Dumka Murgi* are far superior to Kentucky fried chicken. I do not understand why these imported tastes are being rammed down the throat of the nation. That exactly is the point that we are trying to make.

Madam, these chickens are going to be given antibiotics. Will it be good for the health of the people to consume the chicken if it is given a heavy dose of antibiotics? This will not be good for the health of our people. Mr. Digvijay Singh has

rightly pointed out the problems of health that this has led to in America. The Americans are rich. They can meet their problems of health. Can we foot the bill for the health problems to be caused by such junk food? Madam, we raise all these issues and we do not know whether the Government is listening to it or not. We do not know when the Government will respond to it. We would like to know why the Foreign Investment Promotion Board cleared these proposals at such a great speed and in a clandestine manner. Did they call or objections from the environmentalist groups and health groups? All these things should have been done in a very transparent manner. The Government went about this business in a cloak—and—dagger fashion. I, therefore, suggest and plead that all these permissions be stopped forthwith...*(Interruptions)*..

THE DEPUTY CHAIRMAN: Everybody?

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदया मुझे केवल दो मिनट अपनी बात कहनी है। जो मसला दिग्विजय सिंह जी ने उठाया और जयपाल रेड्डी जी ने जिसका समर्थन किया है मैं स्वयं का उससे सम्बद्ध करते हुए कहना चाहती हूं कि मैं उसमें से कोई भी तर्क दोहराना नहीं चाहूंगी जो दिग्विजय जी या रेड्डी जी ने रखे हैं उन सबसे मैं अपनी सहमति प्रगट करते हुए यह कहना चाहती हूं कि जो देश इस समय ब्राजील के बाद फल उत्पादन का सबसे बड़ा देश है और आज के सर्वेक्षण के मुताबिक नम्बर–1 देश मे होने जा रहा है उस देश में गरीब के बच्चे को फल का स्वास्थ्यवर्द्धक रस पिलाने के बजाय यह सरकार पेप्सी कोला पिलाती है। जिस देश में लड्डू मट्ठी पिन्नी खाकर जैसे पकवान प्रचलित है, जो छः-छः महीने बिना खराब हुए रखे जा सकते हैं जिनसे ज्यादा कोई और फास्ट फूड नहीं हो सकता लोग पोटलियों में बांधकर के विदेश में जाते हैं, तो ले जाते हैं, तो मकडोनल बर्गर खिलाये जा रहे हैं। जहां गरीब के लिए भी सत्तू जैसा ऐसा ऐसा खाना प्रचलित है, जो आप वर्षों तक भूनकर चने और जौ को रख सकते हैं और खा सकते हैं और यह भरपेट खाना भी है और स्वास्थ्यवर्धक खाना भी है, तो उस देश में इस तरह का चिकन और मटन का प्रचलन किया जा रहा है। महोदया, मेरे दल ने इसीलिए कंज्यूमन गुड्स उपभोक्ता वस्तुओं में विदेशी पूंजी के आने का विरोध किया था। जिस तरह से जयपाल रेड्डी जी ने कहा कि हम या जो फौरन इंवेस्टमेंट बोर्ड है, वह विदेशी पूंजी के चकाचौंध में इस तरह के जो उनके पास प्रस्ताव आ रहे हैं, उनको पास कर रहा है, हम इसका कड़ा विरोध करते है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि विदेशी पूंजी की चका चौंध में विज्ञापनों के भुलावे में बच्चों के ऊपर इस तरह का असर यह संस्कृति डालेगी कि हमारी जो सादगी की आदत है, वह समाप्त हो जाएगी। हिन्दुस्तान बीमारियों का घर बन जाएगा और जो एंटी बायोटिक्स उन बीमारियों से बचने के लिए चाहिए, वह मुर्गियों को खिला दिए जायेंगे। इसलिए पूरी संस्कृति को तोड़ने का, देश में आरोग्य समाप्त करने का, रोग फैलाने का जो एक नया सिलसिला इस देश को मांसाहारी और पूर मांसाहारी बनाने की प्रक्रिया हिन्दुस्तान की सरकार चला रही है, मैं और मेरा दल इसका सख्त विरोध करते हैं। इस प्रपोजल को तुरन्त समाप्त किया जाए, इस बात की मांग आपके माध्यम से करती हूं। धन्यवाद।

उपसभापति : श्री जगेश देसाई...आप भी खाने की बात कर रहे हैं? आज तो we are not going to have the lunch hour.

SHRI JAGESH DESAI: Madam, Deputy Chairman, I am surprised and pained that in India there are many....

THE DEPUTY CHAIRMAN: Everybody must be feeling hungry now.

SHRI JAGESH DESAI: Madam, the Moti Mahal in Darya Ganj is considered the best for tandoori chicken

and they have also gone abroad to serve their dishes. I am sorry to say that we are inviting multinationals for that purpose. I am not against the multinationals. I make it very clear, but they should be for infrastructure industries like power, communications, transport. I can understand that. If we are going to invite the multinationals for food also, then what will happen to our own people? What will happen to our *halwais?* They will be totally destroyed. I feel that the Government msut take care to see that these kinds of approvals are not given. I am sure that the Government would look into it and invite the multinationals only for infrastructure industries otherwise there will difficult times for this country. As a result of that many people will become unemployed. I fully agree with Digvijay Singhji. The Government must look into it.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Madam, I am on a point of order. We cannot raise all these things before lunch time.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes. I think everybody is feeling hungry now....*(Interruptions)*...

SHRI S. JAIPAL REDDY: Even when we are hungry in India we don't go for junk foods. .. *(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: We eat Idli and Dosa in the Central Hall of Parliament House. ...*(Interruptions)*...

SHRI M. A. BABY: Madam, if we discuss about the "fast food" then we will lose our appetite.

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी : उसका भी कान्ट्रेक्ट यही लोग ले लेंगे। थोड़े दिनों में उसका कान्ट्रक्ट भी इन्हीं लोगों को दे दिया जाएगा।

SHRI ASHOK MITRA (West Bengal): Madam, I endorse what Mr. Desai has said just now because...*(Interruptions)*...the economic liberalisation programme has led to a shrinkage of employment in our country. You take the hundreds of our roadside stalls which offer food. They provide employment to thousands and thousands of our young people and once this M-35 chicken and all that comes and sinks deeply into the psyche of our society then we don't know what will happen to the state of employment. This is the issue which our Government must distinguish whether it is essential or non-essential.

Now, let me mention some other aspect. The other day I read in the papers that a company from Pennsylvani Park, Scot paper Company, is coming here with a 200-billion dollar investment because it wants to manufacture toilet tissues in India and the head of that company has the cheek to say that the biggest challenge for their company is to teach the Indians proper sanitary habits. Are we going to tolerate these kinds of things in the name of inviting more investment? Investment for what? I don't want to say more on this thing, but sooner or later we must ask the Government to spell out its policy where exactly the actual investments are accruing and how much the country is gaining from such investments.

उपसभापति : मलकानी जी, कोई डिश रह गई है, बोलने को ?

SHRI K. R. MALKANI (Delhi): Madam, Deputy Chairperson, I wholly endorse what has been said so far. All kinds of junk foods and junk drinks are invading the country. This is an assault on the health of the country. It is an assault on the culture of our country. We have some of the best dishes in the world. We are the richest in that, perhaps, better than even France and China.

The list is long, i.e., they are *swadisht*. This junk industry, this "fast food" industry must not be allowed to come in. The Government has been less than patriotic, less than nationalist in allowing these junks to come here. They must be thrown out. If they grow, a day will come when they will be boycotted and they will be picketed, I tell you. Even a Surgeon-General of the U.S.A. has made it clear that the Indian food, vegetables, lentils, rice and curd is the best for health. We are giving them a go-by and getting this rotten stuff. It must be stopped. Only today, the Ambassador of a very important country,—I am afraid I am not supposed to name the country,—has offered to assist our farmers, in the name of agriculture. Nobody has asked him for this assistance. Why then this offer of assessment? In the same statement, His Excellency, the Ambassador of that country, says that Indian cereals fetches twice the price of American cereals in the U.S.A. You know that the Punjabi wheat is the best in the world. Why then do you allow the foreign food chains to come into our country at any stage?

I hope the Government will take serious note of the matter. Thank you, Madam.

श्री दिग्विजय सिंह : कम से कम सरसरकार इस बारे में कुछ बोले या सरकार को कनवे किया जाए। Everybody has supported this. The entire House was unanimous on this issue.

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह सारे हाऊस का रेजोल्यूशन है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Everybody agreed, everybody agreed.

श्री चतुरानन मिश्र : (बिहार) : जब गवर्नमेंट रिएक्ट करे, तो एक बात और होगी। मैकडोनल कम्पनी जो पहला खाना बनाएगी, उसको गांधी संग्राहलय में रखवा दें, क्योंकि यह लोग गांधीवादी है। तो इससे सदा के लिए याद रहेगा कि यह अच्छे गांधीवादी हैं। इतना ही इस प्वाइंट पर हमको कहना है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : (उत्तर प्रदेश) : अगले जून में जो पूना और बंगलौर में भारत सरकार ने जो अनुमति दी हैं और जो स्टॉल खुलने जा रहे है, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? .... (**व्यवधान**)

श्री चतुरानन मिश्र : सरकार ही तो उसे बुलवा रही है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : खुलवा रही है, तो प्रतिक्रिया बताएं, उसको रोकें।

श्री सतीश अग्रवाल (राजस्थान) : महोदया, इस सदन में कोई भी ऐसा माननीय सदस्य है क्या, जो दिग्विजय सिंह जी ने और बाकी माननीय सदस्यों ने जो भावना प्रकट की है, उसके विरोध में हो और इसका समर्थन करता हो कि यह आना चाहिए? कोई एक तो खड़ा होकर कह दे कि मैं समर्थन करता हूं। .... (**व्यवधान**) :

श्रीमती सुषमा स्वराज : उनकी पर्सनल फीलिंग तो इस समय बड़ा खाने की हो रही है। .... (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : महोदय, आप पूरे सदन की तरफ से कुछ कह दीजिए, न

उपसभापति : हां, मैं बोल रही हूं। ..... (**व्यवधान**)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA): Madam, I have listened to all the views which have been expressed. I may not make a policy decision or an announcement, but I shall certainly convey the feelings of the House to the Leader of the House and I shall send the proceedings to the Prime Minister who is the Minister for Industrial Development.

SHRI SATISH AGARWAL: What is your personal feelings?

SHRIMATI MARGARET ALVA: I cannot talk about the policies of the Karnataka Government, it is not a Congress Government. It is a different Government there. (*Interruptions*).

SHRI DIGVIJAY SINGH: That is not a proper opinion. But, there is a Government of India there also. What can the State Government do in this affair?

THE DEPUTY CHAIRMAN: We have had enough discussion.

SHRI S. JAIPAL REDDY: When the clearance was given by the Foreign Investment Promotions Board of the Government, the company concerned acquired the legal right to start outlets anywhere.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): The hon. Minister should not have responded. It is her response which created all this. It is better she does not respond.

THE DEPUTY CHAIRMAN: One thing I can assure you. The Railway Minister is sitting here. (*Interruptions*).

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Even if the Central Government has cleared, your State Government has stopped Enron. Why don't you stop here? Why do you bring in the Central Government? Your State Government has brought in spite of the clearance from the Central Government. (*Interruptions*).

SHRI S. JAIPAL REDDY: The contract was entered into by the Government of Maharashtra in regard to Enron. The same legal arrangement is not applicable in regard to food chains. You are trying to confuse the issues. You have no right to stop.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: If it does not suit you, you put the blame on the Central Government.

SHRI S. JAIPAL REDDY: The Government of Karnataka or for that matter any State Government would have no right to stop the outlet. In this the permission has been given by the Government of India.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: In the case of Enron, you have stopped it.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Enron is totally different because the contract was entered into by the M.S.E.B. (*Interruptions*).

SHRI CHATURANAN MISHRA: Madam, I am on a point of order. Mr. Jaipal Reddy says that the State Government cannot stop it. But I think the State Government can stop it.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Yes.

SHRI CHATURANAN MISHRA: You should tell your Government there that this would be bad for health and, therefore, it should be stopped. I think it will be a good thing for India and the people will also come to know that there is a difference between your Government and the earlier Government. (*Interruptions*).

श्री दिग्विजय सिंह : यह सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को भी खराब करेगा। ....(व्यवधान)

उप सभापति : आर्डर, प्लीज। बैठिए, अब कोई बोलेगा नहीं। रेलवे मिनिस्टर यहां बैठे हैं। मैं उनकी तरफ से आश्वासन देती हूं कि वे सेंट्रल हाल में ऐसा खाना नहीं लायेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। वे इडली-डोसा लेकर ही आयेंगे। बस, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल रही हूं। अब चतुरानन मिश्र जी बोलेंगे ...(व्यवधान)...

श्री जगन्नाथ मिश्र : मेरा एक निवेदन है। ...(व्यवधान) ...

श्रीमती फजला सिन्हा : मडम, आपने निर्देश दिया है कि सेंट्रल हाल में नहीं आएंगे। लेकिन क्या सरकार देखें लोग इसको खाते रहेंगे?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I cannot speak on behalf of the Government. I cannot make any policy. That is not my job. You should have discussed it at that time. I must remind Members Just one minute, Chaturanan Mishraji. When the matters are discussed in the House, you do not object to it. You are objecting to it now. At that time, you do not. When the policies are made, nobody speaks on it. You do not make your point clear. Through Special Mentions or Zero Hour Mentions, you shout about it. Neither the Minister of Parliamentary Affairs nor I can change it over here sitting in the Chair. When the policy is made, at that point of time, you must speak. You must give your opinion. You must create public opinion in the country. Then, I am sure, the Central Government would also understand that the people of the country do not want it. Now if only a group of people in the House say that the country does not want it, it is not going to make change. For that, you must create an atmosphere in the country so that the people reject it, the people do not buy it. Then, everybody would close down. The Pizza Hutt and others would close down their shops. They would go. If somebody opens a shop and you buy things from there, it will go on. On the other hand, if you do not buy anything, the shop would close down.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: That is the best, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is the best thing to do. (*Interruptions*).

SHRI H. HANUMANTHAPPA: What about the TV shows? Still they are going on, in spite of the opinion expressed in Parliament. Members from both sides expressed their opinion about these TV shows. But still, things are going on. Nobody takes note of it. Nobody is doing anything about it.

श्री राजनाथ सिंह : मैडम, इस मुद्दे पर सदन के किसी भी सम्मानित सदस्य की असहमति नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसे सदन का सर्वसम्मत प्रस्ताव मान लिया जाए।

श्री चतुरानन मिश्र : इसके लिए मोशन लाना होगा।

उपसभापति : नहीं, सर्वसम्मत प्रस्ताव से कम नहीं होगा। यह सवाल सदन के सिर्फ 244 मेम्बर्स का नहीं है। अगर देश की जनता को फास्ट फूड पसन्द नहीं है तो न खरीदें। अगर वह नहीं खरीदेंगे तो वे अपने आप बन्द करके चले जायेंगे। बैठिए।

श्री राजनाथ सिंह : लेकिन सर्वसम्मत प्रस्ताव होने पर...

उपसभापति : श्री चतुरानन मिश्र।

RE. PATENT AY (AMENDMENT) BILL AND U. S. TRADE LAW 301.

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : उपसभापति महोदया, मैं यह सवाल उठा रहा हूं कि वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन के डाइरेक्टर अभी भारत में आए हुए हैं और हमारी सरकार और व्यापारिक संगठनों से बातचीत भी कर रहे हैं। मेरा यह अनुरोध है कि विपक्ष का इस बारे में जो व्यू प्वाइंट है, इससे सरकार उनको अवगत कराए, क्योंकि सरकार में और विपक्ष में वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन के बारे में और गैट के बारे में मतभेद हैं। इसलिए अच्छा होगा कि सरकार जो विपक्ष की धारणा है, उससे उनको अवगत कराए। अखबारों